स्वच्छ गंगा के लिए मंत्रालयों में सहमति

एमओयू पर हस्ताक्षर

तीन वर्षों के दौरान नदियों में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों पर अंकुश लगाया जाएगा

नई दिल्ली, (भाषा): गंगा को निर्मल एवं अविरल बनाने की नरेन्द्र मोदी नीत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आठ केंद्रीय मंत्रालयों ने एक संयुक्त सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके तीन वर्षों के दौरान गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने और आपसी तालमेल के साथ स्वच्छता पहल को गति प्रदान की जायेगी।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस सहमति पत्र को 30 जनवरी 2016 को अमलीजामा पहनाया गया। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

सहमति पत्र के अनुसार, गंगा को अविरल एवं निर्मल बनाने के लिए सात मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है साथ ही 21 कार्य बिन्दु तय किये गए हैं। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने 2015 से 2020 के दौरान करीब 20 हजार करोड़ रुपये का कार्यक्रम तय किया है जिसमें 12728 करोड़ रुपये नये कार्यक्रमों के लिए तथा 7272 करोड़ रुपये अभी जारी कार्यक्रमों के लिए हैं। नमामि गंगे परियोजना का 100 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।

रेल मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के बीच हुए सहमति पत्र के मुताबिक, दोनों पक्षों ने गंगा-यमुना नदी क्षेत्र पर स्थित जल शोधन संयंत्रों से शोधित जल की आपूर्ति और उपयोग (पीने के लिए नहीं) करने पर सहमति व्यक्त की है।

जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय का काम करेगा। वह शोधित जल के उपयोग के लिए बाजार का विकास करेगा। यह योजनाओं को लागू करने के लिए शीर्ष मंत्रालय होगा और नमामि गंगे परियोजना के लिए राज्य सरकारों के साथ भी समन्वय स्थापित करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय साफ सफाई, जैव विविधता की जरूरत के बारे में जागरूकता और पर्यावरण साक्षरता फैलायेगा।

पूर्वोत्तर में भूकंप के दो हल्के झटके

नई दिल्ली। मंगलवार तड़के देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता क्रमशः 3.7 और 3.8 मापी गई। भूमि विज्ञान मंत्रालय से संबद्ध राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर 3.8 की तीव्रता का भूकंप सोमवार देर रात 1.18 बजे भारत-म्यांमार सीमा पर आया।

नमामि गंगे से भाजपा सांसद नाखुश

हिं - 3-2-16

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

अफसरों से पूछा, 30 साल में क्या किया

समिति ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के अफसरों से पूछा कि आखिर 30 साल में क्या किया। उसका नतीजा क्या रहा। भविष्य में नमामि गंगे पर क्या काम चल रहा है। अभाव और सुझाव भी बताए। उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के मेम्बर सेक्रेटरी एस.सी.यादव ने रिपोर्ट के जरिए रिपोर्ट रखी तो डा.जोशी ने बीच-बीच में कई सवाल उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि 2030 तक वर्तमान स्थिति को देखे तो लगभग 7301 एमएलडी का ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत होगी।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व वाली 30 सांसदों की इस्टीमेट कमेटी ने प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे की प्रगति पर सवाल खड़े कर दिए। डॉ. जोशी ने दो टूक कहा कि ऐसे तो 50 साल में गंगा साफ नहीं हो पाएगी। गंगा पर अंतरराष्ट्रीय चिंता है। धरातल पर काम न हुआ तो नमामि गंगे ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। युद्ध स्तर पर प्रोजेक्ट नहीं स्वच्छ गंगा को मिशन मान कर काम करना होगा।

कानपुर पहुंची इस्टीमेट कमेटी ने मंगलवार को नमामि गंगे प्रोजेक्ट की समीक्षा की। कमेटी के चेयरमैन डा.जोशी ने 1985-2015 तक गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गए काम का नतीजे पर केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, जलनिगम के अधिकारियों को खरी-खरी सुनायी। सांसदों ने कहा गंगा सफाई के नाम पर बने पहले सभी प्रोजेक्ट फेल हो चुके हैं। करोड़ों रुपए पानी में बह गए। यही हाल अफसर नमामि गंगे प्रोजेक्ट का कर रहे हैं। डॉ. जोशी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर भी जिस तरह काम चल रहा है पांच साल तो क्या 50 सालों में भी गंगा साफ नहीं हो पाएगी। भौतिक प्रगति ही गंगा को प्रदूषण मुक्त करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा जब तक अविरल नहीं होगी उसको निर्मल नहीं किया जा सकता है।

डॉ. जोशी ने कहा कि टेनरियों को ज्यादा बदनाम किया जाता है। ऐसी तकनीक बतानी होगी जिससे क्रोम व जहरीले पदार्थ न निकलें या उनका विकल्प तलाश लिया जाए। तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। प्रदूषण फैलाने वाली कोई भी चीज सख्ती के साथ न जाने दी जाए।

7 फरवरी को हो सकती है हल्की बारिश

हि-3-2-16

नगर संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में आने वाले दिनों में बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग ने 7 फरवरी को हल्की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही, दिल्ली में अगले दो से तीन दिनों तक सुबह के वक्त टेंपरेचर दो डिग्री तक कम हो सकता है। आज आसमान साफ रहेगा। सुबह के वक्त हल्का कोहरा छा सकता है। मैक्सिमम टेंपरेचर 22 डिग्री और मिनिमम टेंपरेचर 7 डिग्री रहने का अनुमान है। मंगलवार को अच्छी धूप खिली। मौसम भी सामान्य रहा। मैक्सिमम टेंपरेचर 21.3 डिग्री दर्ज हुआ, जो नॉर्मल से एक डिग्री कम है। मिनिमम टेंपरेचर नॉर्मल से दो डिग्री कम के साथ 6.6 डिग्री दर्ज हुआ। हवा में मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 100 पर्सेंट दर्ज हुई। दिन भर कई कई इलाकों में तेज स्पीड से हवा चली।

मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि देश के उत्तरी इलाके में पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहुंचा है, जिससे मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में उत्तर से नमी वाली हवा पहुंच रही है। इससे मौसम चेंज हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि अगले दो से तीन दिनों तक दोपहर के समय लोगों को अच्छी धूप मिल सकती है। 6 फरवरी को हिमालय रीजन में एक और नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देगा। इससे पूर्वी दिशा से भी नमी वाली हवा दिल्ली की तरफ मूव करेगी। इससे दिल्ली में 7 फरवरी को हल्की बारिश होने की उम्मीद है। उस दिन आसपास मैक्सिमम टेंपरेचर 23 डिग्री और मिनिमम टेंपरेचर 11 से 12 डिग्री रहने का अनुमान है।

हिं- 3-2-16

गंगा की सफाई के लिए 8 मंत्रालय एकजुट

सहमति के बाद 21 सूत्री योजना बनाई गई

प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

गंगा की सफाई के लिए आठ मंत्रालय एकजुट हो गए हैं। इस सिलसिले में इनके बीच सहमति पत्र पर दस्तखत भी हुए हैं। इसके मुताबिक, आठों मंत्रालय तीन साल में गंगा को एक बार फिर उसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये मंत्रालय हैं- नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, मानव संसाधन विकास, स्वच्छता एवं पेयजल, ग्रामीण विकास, पर्यटन, आयुष, युवा एवं खेल मामले और पोत परिवहन मंत्रालय। सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए 2015 से 2020 के बीच 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। गंगा को साफ करना एनडीए की प्राथमिकता में है। उसने इस परियोजना का पूरा खर्चा खुद उठाने का फैसला किया है। सहमति पत्र के मुताबिक, गंगा को निर्मल बनाने के लिए 7 वर्किंग पॉइंट्स तय किए गए हैं और 21 सूत्री प्रोग्राम बनाया गया है। इसे सभी 8 मंत्रालय आपसी तालमेल से पूरा करेंगे। गंगा संरक्षण मंत्रालय सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाने का काम करेगा।

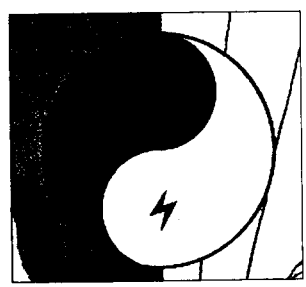

स्वच्छ भारत मिशन का नतीजा अगले हफ्ते : प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से 'स्वच्छ भारत मिशन' का रिजल्ट अगले हफ्ते आ सकता है। इससे यह पता चलेगा कि यह प्रोजेक्ट कितना कामयाब हुआ है। यह रिजल्ट इस मायने में अहम है कि इससे पता चलेगा कि मोदी की योजनाओं का जमीन पर कोई असर हो भी रहा है या नहीं। चूंकि खुद मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। **(विस)**

- एचआरडी मिनिस्ट्री साफ-सफाई के साथ ही जैव विविधता की जरूरत के बारे में गंगा किनारे के इलाकों में जागरूकता और पर्यावरण साक्षरता का प्रसार करेगी।
- रेल और जल संसाधन मंत्रालय गंगा और यमुना किनारे बने जल शोधन संयंत्रों से साफ पानी की सप्लाई (पीने के लिए नहीं) करने पर राजी हुए हैं।
- जल संसाधन मंत्रालय इस पानी के लिए बाजार का विकास करेगा।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा और अन्य परियोजनाओं को गंगा सफाई की मुहिम से जोड़ेगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय गांवों में बनवाएगा।
- पर्यटन मंत्रालय इकॉलजी को बेहतर बनाने के उपायों के साथ ही इको टूरिजम को प्रोत्साहित करेगा। आयुष मंत्रालय गंगा के तटीय क्षेत्रों में औषधीय पौधों के विकास का काम करेगा।
- पोत परिवहन मंत्रालय नदी परिवहन की आधारभूत संरचना तैयार करेगा।
- युवा एवं खेल मंत्रालय गंगा की सफाई और वनीकरण को बढ़ावा देगा।

The Times of India
Title : NGT won't quash green nod to dam
Author :
Location :
New Delhi:
Article Date : 02/03/2016

The capital's The capital's water woes may soon come to an end with the National Green Tribunal on Tuesday giving its nod to the 40 MW Renuka Hydro-Power Project in Himachal Pradesh and refusing to quash the environmental clearance granted to it.